

# My Notes.....

## राष्ट्रीय

### भुखमरी वैश्विक सूची में भारत का स्थान

भारत भुखमरी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ऐसे 119 देशों की वैश्विक सूची में भारत 100वें स्थान पर है। इस मामले में उत्तर कोरिया, बांग्लादेश और इराक से भारत पिछड़ गया है लेकिन राहत की बात यही है कि पाकिस्तान की तुलना में इसकी स्थिति बेहतर है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले वर्ष भारत इस सूची में 97वें स्थान पर था।

#### क्या है

- बच्चों में कृपोषण की स्थिति गंभीर होने से देश में भुखमरी की गंभीर स्थिति है। इसपर काबू पाने के लिए सामाजिक क्षेत्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता की दरकार है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआई) ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक क्षेत्र पर बल देने के लिए कहा है।
- आइएफपीआरआई ने एक बयान में कहा है, '119 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है और एशिया के सभी देशों में से दो की स्थिति इससे ज्यादा गंभीर है। एशिया के केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान बेहद खराब देशों में शामिल हैं।'
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपने कई पड़ोसी देशों चीन (29वां), नेपाल (72वां), म्यांमार (77वां), श्रीलंका (84) और बांग्लादेश (88वां) से नीचे आया है।
- पाकिस्तान 106वें और अफगानिस्तान 107वें स्थान पर हैं। उत्तर कोरिया 93वें, जबकि इराक 78वें स्थान पर हैं।

#### क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स?

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी को मापने का एक पैमाना है जो वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भुखमरी को प्रदर्शित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute& IFPRI) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले इंडेक्स में उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर तक पहुँच चुके हैं, जहाँ भुखमरी नगण्य मात्रा में है।
- इंडेक्स में शामिल न किये जाने वाले देशों में पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, अमेरिका, कनाडा इत्यादि शामिल हैं।
- साथ ही कुछ ऐसे अल्प विकसित देश भी इस इंडेक्स से बाहर रहते हैं जिनके भुखमरी संबंधी आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते या अपर्याप्त होते हैं, जैसे बुरुंडी, इरीट्रिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया आदि।

### पिछड़ों में अति पिछड़ा खोजने को आयोग गठित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग में उप वर्गीकरण के परीक्षण के लिए आयोग गठित किया है। इस आयोग की अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जज जी. रोहिणी होंगी। आयोग का काम अन्य पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े तबकों की पहचान करना होगा ताकि इस वर्ग में शामिल जातियों में से वर्चितों को आरक्षण का लाभ दिलाया जा सके। इससे सरकार के ओबीसी आरक्षण का उप वर्गीकरण के द्वारा आरक्षण का दायरा विस्तृत करने और सबको सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के निश्चय को बल मिलेगा।

#### क्या है

- राष्ट्रपति की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत की व्यवस्था के अनुरूप आयोग का गठन कर दिया है।

2. यह फैसला महात्मा गांधी की सबको सामाजिक न्याय दिलाने की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारने और पिछड़े वर्ग में सभी को न्याय दिलाने के सरकार के प्रयासों के तहत किया गया है।
3. इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा डॉ. जे.के. बजाज सदस्य होंगे जबकि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक, जनगणना विभाग के आयुक्त और महापंजीयक पदेन सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस आयोग के सचिव होंगे।
4. आयोग केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों और समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के समान वितरण का परीक्षण करेगा। वह ओबीसी में उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक तरीके से मानक, शर्तें और तंत्र के बारे में विचार करेगा। इसके साथ ही आयोग ओबीसी की केंद्रीय सूची से जातियों और समुदायों की पहचान कर उन्हें उपर्याप्त में शामिल करने का काम करेगा।
5. आयोग को रिपोर्ट तैयार कर तीन महीने में राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं और संस्थानों में हर स्तर पर ओबीसी आरक्षण को न्यायसंगत रूप से वितरित करने के तरीके और साधनों पर विचार करेगी।

### **त्रिभाषा फॉर्मूले से बाहर होंगी विदेशी भाषाएं**

अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में जर्मन और फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं त्रिभाषा फॉर्मूले का हिस्सा नहीं होंगी। माना जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा है कि जो विद्यार्थी विदेशी भाषाएं सीखने के इच्छुक हैं उन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में चौथी भाषा का चयन करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, 'संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाएं ही त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत सिखाई जानी चाहिए।' इस संबंध में सीबीएसई के साथ विचार-विमर्श जारी है और अगले शैक्षणिक सत्र से बदलावों को लागू किए जाने की संभावना है।

**क्या है**

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** के तहत, त्रिभाषा फॉर्मूले का आशय है कि हिंदीभाषी राज्यों में विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। जबकि गैर-हिंदीभाषी राज्यों में उन्हें स्थानीय भाषा और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी सीखनी चाहिए। हालांकि, 18 हजार से संबद्ध संस्थानों में से ज्यादातर आठवीं तक मातृभाषा या हिंदी, अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा सिखाते हैं।
2. दरअसल, पिछले साल दिसंबर में सीबीएसई ने माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा था। इसके बाद से ही प्रयास लगाए जा रहे थे कि नई योजना को कब से लागू किया जाएगा।
3. इस प्रस्ताव और सीबीएसई के वर्तमान त्रिभाषा फॉर्मूले में दो बड़े अंतर हैं। पहला, नई योजना आठवीं की बजाय दसवीं तक लागू होगी। दूसरा, इसमें विदेशी भाषा सम्मिलित नहीं होगी।
4. केंद्रीय विद्यालयों की 1968 की त्रिभाषा नीति के मुताबिक जिस राज्य में स्कूल है उस राज्य की भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी क्रमशः पहली व दूसरी भाषाएं रहेंगी।
5. जिन राज्यों की अधिकारिक भाषा हिंदी है, वहां तीसरी भाषा संस्कृत होगी। 2011 में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जर्मनी के साथ समझौता किया जिसके तहत जर्मन को केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी अनिवार्य भाषा का दर्जा मिला। इसके बदले में जर्मन सरकार के गोथे संस्थान ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को 700 जर्मन शिक्षक दिए।
6. नवंबर, 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईशनी ने इस मामले की जांच करने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस समझौते के नवीनीकरण को रोक दिया और जर्मन को तीन अनिवार्य भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया। जर्मन को विदेशी भाषाओं की सूची में रखा गया है।

### **पहले बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का उद्घाटन**

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों पहली चार दिवसीय बिम्सटेक देशों की आपदा प्रबंधन अभ्यास-2017 का उद्घाटन किया गया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने साझा अभ्यास में शामिल होने आए बिम्सटेक देशों के प्रतिनिधियों

का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपकी उपस्थिति आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वर्ष मानसून सत्र में बाढ़, भूस्खलन ने काफी तबाही मचायी है, जिससे बिम्सटेक देशों के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इन घटनाओं ने आपदा प्रबंधन में साझा सुधार की ओर ध्यान दिलाया। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 1996 से 2015 के दरम्यान बिम्सटेक देशों में करीब 317,000 लोगों की आपदा में मौत हुई है। इस दौरान करीब 16 मिलियन लोग बेघर हुए।

### क्या है

1. राजनाथ सिंह की ओर से इन आपदाओं के लिए जलवायु परिवर्तन को एक अहम वजह बताया गया, जिसकी वजह से बाढ़, सूखा, लू, समुद्री तूफान आते हैं। इसके चलते बिम्सटेक देशों को जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान देने के साथ ही राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर काम करने की बात दोहराई।
2. राजनाथ सिंह ने कहा कि बीते दो दशकों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ देशों ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने समुद्री तूफान से निपटने में बांग्लादेश के कारगर कदमों की सराहना की।
3. बांग्लादेश के इस प्रयासों को वैश्विक स्तर पर कारगर माना गया है। थाईलैंड में सुनामी के वार्निंग सिस्टम की अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात कही गई। उनकी ओर से फैलिन और हुदहुद के दौरान उठाए के सुरक्षा कदमों की जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में सुनामी की तत्काल वार्निंग के सिस्टम को विकसित किया जा रहा है।
4. गैरतलब है कि इस साल सात फरवरी को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न 17वें बिम्सटेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारत इस क्षेत्र में पहले वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन करेगा।
5. बिम्सटेक के सात सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। यह अभ्यास बिम्सटेक के सदस्य देशों के लिए आपदा जोखिम कटौती (डीआरआर), आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक उपयोगी मंच साबित होगा।
6. यह 10 से 13 अक्टूबर तक दिल्ली और एनसीआरएफ द्वारा आयोजित किया जाएगा।

### आईएएलए का दर्जा बदला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एण्ड लाइट हाउस अथॉरिटीज (आईएएलए) को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से बदलकर अन्तः सरकारी संगठन (आईजीओ) किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव से ‘पोतों के सुरक्षित, मितव्यी और दक्षतापूर्ण आवागमन’ की सुविधा होगी। इससे आईएएलए अन्तर्राष्ट्रीय मेरीटाईम संगठन (आईएमओ) व इन्टरनेशनल हाइड्रोग्राफिक आर्गेनाइजेशन (आईएचओ) के समकक्ष हो जाएगा।

### पृष्ठभूमि

1. आईएएलए का मुख्यालय फ्रांस कानून के अन्तर्गत सेंट जर्मेनैन लाए (फ्रांस) में 1957 में स्थापित किया गया था।
2. यह 83 राष्ट्रीय सदस्यों वाली एक आम सभा द्वारा प्रशासित है, और अधिशासी तंत्र के रूप में एक परिषद कार्यरत है।
3. आईएएलए परिषद में 24 राष्ट्रीय सदस्य हैं और भारत इसकी परिषद का एक सदस्य है जिसका प्रतिनिधित्व महानिदेशक-लाइट हाउस एवं लाइटशिप्स (डीजीएलएल) नौवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लाइटहाउस

अधिनियम 1927 के अनुसार डी जी एल एल अण्डमान और निकोबार और लक्ष्मीप समूहों सहित भारत के तटों पर सामान्य स्थितियों में नौचालन की गतिविधियों का अनुरक्षण में मदद प्रदान करता है।

4. मई 2014 में ला कोर्नना में आयोजित अपने ग्यारहवें सत्र ने इन्टरनेशनल एसोसिएशन आफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एण्ड लाईटहाऊस अथॉरिटिज (आईएएलए) की आम सभा ने एक संकल्प को अंगीकार किया था, जिसमें उसने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया था कि आईएएलए का दर्जा एनजीओ से बदलकर आई एएलए किए जाने से 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी मदद होगी।

## प्रस्तावित नई हज नीति

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली राहत के बाद मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को एक और तोहफा देने जा रही है। नई हज नीति के तहत मुस्लिम महिलाएं बिना किसी मेहरम (पुरुष जिसके साथ खून का रिश्ता हो) के भी स्वतंत्र रूप से हज यात्रा कर सकेंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नई नीति के तहत हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

**क्या है**

1. अभी तक कोई भी मुस्लिम महिला अपने खून के रिश्ते वाले रिश्तेदार के बिना हज पर नहीं जा सकती थी।
2. नई नीति के तहत, 45 साल की उम्र पार चुकी चार या उससे अधिक मुस्लिम महिलाएं एक साथ हज यात्रा पर जा सकती हैं। सऊदी अरब भी 45 और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को हज के लिए प्रवेश की अनुमति देता है।
3. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए नई हज नीति में सबसिडी की व्यवस्था खत्म करने को भी हरी झंडी दे दी गई है।
4. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक धीरे-धीरे हज सबसिडी खत्म करने का आदेश दिया था। मगर सरकार गरीब मुसलमानों को हज यात्रा का सस्ता विकल्प मुहैया कराने पर विचार कर रही है।
5. इसके लिए समुद्री जहाज से यात्रा की सुविधा दी जा सकती है। सरकार इसके लिए सऊदी अरब से बात करेगी, साथ ही अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जरूरी टेंडर भी मंगाएंगी। अभी तक सिर्फ हवाई जहाज से हज यात्रा संभव थी, जो काफी महंगी होती है।
6. नई नीति में हज यात्रियों को देश में बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए हज रवानगी स्थलों की संख्या 21 से घटाकर नौ की जाएगी। इनमें दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु और कोच्चि शामिल हैं। इन जगहों पर सरकार अत्यधुनिक सुविधाओं से लैस हज हाऊस का निर्माण करेगी। जो प्रस्थान स्थल इस सूची से बाहर हैं, वहां हज यात्रियों के लिए बनी सुविधाओं का इस्तेमाल शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
7. सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्ला की अध्यक्षता में नई हज नीति पर सुझाव देने के लिए समिति बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
8. मुख्तार अब्बास नकवी ने नई हज नीति को पारदर्शी और जनता के अनुकूल बताया है। इसमें हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों के अनुपात को भी साफ कर दिया गया है।
9. इसके तहत 70 फीसदी यात्री हज समिति के जरिए और 30 फीसदी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए जाएंगे।

## देश का पहला डंपिंग यार्ड विहीन शहर

डंपिंग यार्ड यानी वह जगह जहां शहर भर के कचरे को एकत्र किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में डंपिंग यार्ड नहीं हैं। यह देश का पहला डंपिंग यार्ड विहीन शहर बन गया है। अंबिकापुर के कचरा प्रबंधन मॉडल को देश के लिए रोल मॉडल करार दिया गया है। गत दिवस गांधी जयंती पर इस मॉडल को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया

गया। इसकी एक खूबी यह भी है कि यह पूरा सिस्टम महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। सेकड़ों महिलाओं को इससे रोजगार प्राप्त हुआ है।

**क्या है**

1. दिल्ली में पहाड़नुमा डिपिंग यार्ड के धसकने से हाल ही एक बड़ा हादसा हुआ था। इस घटना ने महानगरों में डिपिंग यार्ड की समस्या को नए सिरे से रेखांकित किया।
2. कचरा प्रबंधन के अंबिकापुर मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें डिपिंग यार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही नहीं, अंबिकापुर देश का पहला शहर है, जहां डिपिंग यार्ड नहीं है।
3. पुराना डिपिंग यार्ड अब खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया गया है। अब यहां कहीं भी कचरे का ढेर नहीं लगाया जाता। हालांकि इस शहर की आबादी कम है, लेकिन इस स्तर के अन्य शहरों की अपेक्षा यह अब्बल स्थान पर है। कचरा प्रबंधन का इसका मॉडल देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देशभर में इसे अपनाया जाना है।
4. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और सॉलिड एंड लिविंग रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएलआरएम) यानी सूखे और गीले कचरे को छांटकर अलग करना, इन दो प्रक्रियाओं पर आधारित है यह मॉडल।
5. इसकी शुरुआत यहां दो साल पहले हुई थी। तत्कालीन कलेक्टर ऋतु सेन ने इसकी योजना बनाई थी। इसके तहत निगम के 48 वार्डों में स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति का गठन किया गया। इसकी सभी सदस्य महिलाएं हैं।
6. इसमें 500 से अधिक महिलाओं को घर-घर जाकर कचरा संग्रहण का जिम्मा सौंपा गया है। ये महिलाएं हर दिन घर-घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं। हरे रंग की साड़ी, मास्क और दस्ताने पहनीं ये महिलाएं इलेक्ट्रिक रिक्शेनुमा ट्रॉली वाले वाहन पर सवार हो इस काम को तत्परता से अंजाम देती हैं।
7. इसके बाद 17 एसएलआरएम सेंटरों में कचरे को पहुंचाती हैं। जहां कचरे की छंटाई की जाती है। गीले कचरे को खाद में तब्दील कर दिया जाता है। और सूखे कचरे को रिसाइकिल करने के लिए कबाड़ में बेच दिया जाता है।

## केंद्र सरकार ने किया इच्छा मृत्यु का विरोध

क्या किसी शख्स को ये अधिकार दिया जा सकता है कि वह यह कह सके कि कोमा जैसी स्थिति में पहुंचने पर उसे जबरन जिंदा न रखा जाए? लाइफ सपॉर्ट सिस्टम हटाकर उसे मरने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि अगर इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। गौरतलब है कि एक एनजीओ कॉमन कॉर्ज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इच्छा मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर मरणासन का सपॉर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है।

**क्या इच्छा मृत्यु मूल अधिकारों के दायरे में है**

1. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ

## पैसिव यूथनेशिया का समर्थन किया

1. एनजीओ कॉमन कॉर्ज ने 2005 में इस मसले पर याचिका दाखिल की थी। कॉमन कॉर्ज के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को लिविंग विल बनाने का हक होना चाहिए।
2. 'लिविंग विल' के माध्यम से शख्स यह बता सकेगा कि जब वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, जहां उसके ठीक होने की उम्मीद न हो, तब उसे जबरन लाइफ सपॉर्ट सिस्टम पर न रखा जाए।
3. प्रशांत ने स्पष्ट किया कि वह ऐक्टिव यूथनेशिया की वकालत नहीं कर रहे, जिसमें लाइलाज मरीज को इंजेक्शन दे कर मारा जाता है।
4. वह पैसिव यूथनेशिया की बात कर रहे हैं, जिसमें कोमा में पड़े लाइलाज मरीज को वेटिलेटर जैसे लाइफ सपॉर्ट सिस्टम से निकाल कर मरने दिया जाता है।

- ने सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ कुत्रिम सपॉर्ट सिस्टम पर जीने को मजूबर किया जा सकता है?
2. जब सम्मान से जीने को अधिकार माना जाता है तो क्यों न सम्मान के साथ मरने को भी अधिकार माना जाए? क्या इच्छा मृत्यु मौलिक अधिकार के दायरे में आती है?
  3. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल मध्यम वर्ग में बृद्ध लोगों को बोझ समझा जाता है। ऐसे में इच्छा मृत्यु में कई दिक्कतें हैं।

### **कैसे तय होगा, मरीज ठीक नहीं हो सकता**

1. इस पर अदालत ने सवाल किया कि आखिर यह कैसे तय होगा कि मरीज ठीक नहीं हो सकता? प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि ऐसा डॉक्टर तय कर सकते हैं। फिलहाल कोई कानून न होने की वजह से मरीज को जबरन लाइफ सपॉर्ट सिस्टम पर रखा जाता है।
2. कोमा में पहुंचा मरीज खुद इस स्थिति में नहीं होता कि वह अपनी इच्छा व्यक्त कर सके इसलिए उसे पहले ही ये लिखने का अधिकार होना चाहिए कि जब उसके ठीक होने की उम्मीद खत्म हो जाए तो उसके शरीर को यातना न दी जाए।

### **लिविंग विल आत्महत्या की तरह**

1. केंद्र ने कहा कि मामले में गठित की गई कमिटी ने विशेष परिस्थितियों में पैसिव यूथनेशिया (कोमा में पड़े मरीज का लाइफ सपॉर्ट सिस्टम हटाने) को सही बताया है, लेकिन लिविंग विल का सरकार समर्थन नहीं करती। ये एक तरह से आत्महत्या जैसा है।
2. इस मामले की सुनवाई कर रही पांच सदस्यीय संविधान बैंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। इस बैंच में जस्टिस ए.के. सिकरी, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। गैरतलब है कि लगभग 35 साल से कोमा में पड़ी मुंबई की नर्स अरुणा शानबांग को इच्छा मृत्यु देने से सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इनकार कर दिया था।

### **SC का बड़ा फैसला**

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म समझा जाएगा। इस फैसले के साथ कोर्ट ने 11 अक्टूबर को 15 से 18 साल की नाबालिंग पत्नी से संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी से छूट देने वाली आईपीसी की धारा 375 के अपवाद (2) को खारिज कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल की नाबालिंग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर दुष्कर्म का मुकदमा चल सकता है। मगर कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पर दुष्कर्म का मुकदमा तभी चलेगा, जब पत्नी एक साल के भीतर शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं कोर्ट का यह फैसला आगे से लागू होगा। पुराने केस इससे प्रभावित नहीं होंगे।

**क्या है**

1. एक गैर सरकारी संस्था इन्डिपेंडेंट थाट ने धारा 375 (2) को शादीशुदा और गैर शादीशुदा 15 से 18 वर्ष की लड़कियों में भेदभाव करने वाला बताते हुए रद करने की मांग की थी।
2. आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत 15 से 18 वर्ष की नाबालिंग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाता था।
3. एनजीओ ने कहा था कि नाबालिंग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में आना चाहिए। वकील गैरव अग्रवाल ने कहा, हम 18 साल से कम की किसी लड़की को पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चे के रूप में देखते हैं, लेकिन एक बार उसकी शादी हो जाने के बाद उसे ही आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत बच्चा नहीं मानते हैं। यह पूरी तरह से अनुचित है।

4. 15 साल से कम की लड़की को बच्ची के रूप में ही देखा जाना चाहिए, चाहें उसकी शादी हुई हो या नहीं। संसद को बच्चे की रक्षा करनी ही होगी। उन्होंने कहा, जिस तरह से बालिग होने की उम्र 18 साल तय की गई है उसी तरह से संबंध बनाने के लिए महिला की सहमति की उम्र भी 18 साल लागू होनी चाहिए।
5. सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए सामाजिक परिवेश की दुहाई दे कहा था कि गैरकानूनी होने के बावजूद बाल विवाह अभी भी प्रचलित हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि बाल विवाह सामाजिक सच्चाई है और इस पर कानून बनाना संसद का काम है। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
6. उल्लेखनीय है कि आईपीसी 375 (2) कानून का अपवाद कहता है कि अगर 15 से 18 साल की पत्नी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए।

## भारतीय जल सप्ताह-2017 का उद्घाटन

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 10 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में भारतीय जल सप्ताह-2017 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन का आधार है। यह अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल का मुद्दा जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जल का बेहतर और अधिक प्रभावी इस्तेमाल भारतीय कृषि और उद्योग के लिए एक चुनौती है। हमारे लिए यह आवश्यक कर देता है कि हम अपने गांवों और निर्मित होने वाले शहरों में नए मानदंड स्थापित करें।

### क्या है

1. राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में भारत में 80 प्रतिशत जल का इस्तेमाल कृषि के लिए और केवल 15 प्रतिशत उद्योग द्वारा किया जाता है। आने वाले वर्षों में यह अनुपात बदलेगा। जल की कुल मांग बढ़ेगी।
2. जल के इस्तेमाल और उसके दोबारा इस्तेमाल की क्षमता को औद्योगिक परियोजनाओं का खाका तैयार करते समय उसमें शामिल किया जाना चाहिए। व्यवसाय और उद्योग को इस समाधान का हिस्सा बनना चाहिए।
3. राष्ट्रपति ने कहा कि शहरी भारत में हर वर्ष 40 अरब लीटर बेकार पानी निकलता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस पानी के जहरीले तत्वों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाई जाए और इसका इस्तेमाल सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए किया जाए। यह किसी भी शहरी योजना कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
4. राष्ट्रपति ने ऐसा जल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जो स्थानीय लोगों के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि यह गांवों और पड़ोसी समुदायों को शक्ति सम्पन्न बनाए और उनमें ऐसी क्षमता का निर्माण करे कि वे अपने जल संसाधनों का प्रबंधन, उनका आंवटन और मूल्यांकन कर सकें।
5. 21वीं सदी की किसी भी नीति में पानी के मूल्य की संकल्पना के तत्व को शामिल किया जाना चाहिए। यह समुदायों सहित सभी साझेदारी को प्रोत्साहित करे कि वे अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और जल की मात्रा से लेकर लाभों के परिमाण को आवंटित करने का क्रम चिन्हित करें।
6. राष्ट्रपति ने कहा कि जल तक पहुंच मनुष्य के गौरव का पर्याय है। भारत में जनसंख्या को पीने का सुरक्षित जल प्रदान करने का कार्य 600 हजार गांवों में फैला हुआ है और केवल शहरी क्षेत्र ही परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं है। यह एक पावन प्रतिबद्धता है।
7. सरकार ने सभी गांवों में 2022 तक पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की एक रणनीतिक योजना तैयार की है, जब भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। तब तक इस लक्ष्य के अंतर्गत 90 प्रतिशत गांवों में रहने वाले परिवारों को पाइप लाइन के जरिए पानी की आपूर्ति मिलने लगेगी। हम विफल नहीं हो सकते।

## 'जीवमृतम' लांच

कोल्लम के बलीककावू स्थित मठ के मुख्यालय में 8 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता अमृतानंदमयी मठ के 100 करोड़ रुपये की लागत वाले स्वच्छ जल अभियान 'जीवमृतम' को लांच किया। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली बार कोविंद दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने फिल्टर सिस्टम 'जीवमृतम' का उद्घाटन किया जो देश के 10 मिलियन ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराएगा।

**क्या है**

1. अम्मा के नाम से प्रसिद्ध माता अमृतानंदमयी देवी के 64वें जन्मदिवस समारोह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
2. अमृतानंदमयी देवी की उपस्थिति में इस पहल को लांच करते हुए कोविंद ने कहा, मानवता की सेवा ही परमात्मा की महान सेवा है।
3. लद्दाख स्काउट्स रेजीमेंटल सेंटर और लेह के सीमावर्ती शहर में रेजीमेंट के पांच बटालियन में अपने दौरे को याद करते हुए, कोविंद ने कहा, 'एक हाथ में हमारे जवानों की बहादुरी है और दूसरे में हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का सहयोग, प्यार के दो मोटे खंभे हैं जिसपर हमने अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया है।'
4. केरल के आदि शंकराचार्य, श्री नारायण गुरु और अद्यानकली जैसे आध्यात्मिक व समाज सुधारकों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह राज्य देश के आध्यात्मिक राज्यों में से एक है।
5. मठ अधिकारियों के अनुसार, जीवमृतम प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण के तहत विशेष तौर पर डिजायन किए गए फिल्टर सिस्टम को स्वच्छ पेय जल के लिए 5,000 गांवों में इंस्टॉल किया जाएगा।

## रेलवे ने खत्म किया 36 साल पुराना प्रोटोकॉल

रेलवे में वीआइपी संस्कृति खत्म करने की पहल करते हुए रेल मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से दफ्तर और घर दोनों जगहों से इसे समाप्त करने के लिए कहा है। इस दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मंत्रालय ने 36 साल पुराने एक प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है। इसके तहत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के अन्य सदस्यों की क्षेत्रीय यात्राओं के दौरान उनके आगमन और प्रस्थान के समय महाप्रबंधकों ( जीएम ) का उपस्थित रहना अनिवार्य था।

**क्या है**

1. मंत्रालय ने 28 सितंबर को एक आदेश जारी कर इस तरह के प्रोटोकॉल वाले 1981 के सर्कुलर को वापस ले लिया है।
2. यही नहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों से सैलून और एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने की बजाय स्लीपर और एसी थ्री-टीयर में अन्य यात्रियों के साथ सफर करने को कहा है।
3. इन वरिष्ठ अधिकारियों में रेलवे बोर्ड के सदस्य, रेलवे जोनों के महाप्रबंधक और सभी 50 मंडलों के प्रबंधक शामिल हैं। इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अशवनी लोहानी ने कहा है कि अब किसी भी अधिकारी को गुलदस्ते और उपहार नहीं दिए जाएंगे।
4. वरिष्ठ रेल अधिकारियों को दफ्तर में ही नहीं बल्कि घर पर भी वीआइपी संस्कृति का परित्याग करना होगा। अब सभी आला अधिकारियों को अपने घरों में घरेलू कार्यों में लगे रेलवे के समस्त कर्मचारियों को मुक्त करना होगा।
5. वरिष्ठ रेल अधिकारियों के घरों पर करीब 30 हजार ट्रैकमैन काम करते हैं। उन्हें ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया है।
6. मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि पिछले एक महीने में छह से सात हजार कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'किसी को भी ड्यूटी पर वापस लौटने के निर्देश से छूट नहीं दी जाएगी। केवल बहुत विशेष परिस्थितियों में यह छूट मिल सकेगी। उम्मीद है कि सभी कर्मचारी जल्द काम पर लौटेंगे।'

## अन्तर्राष्ट्रीय

### ‘पोटाला पैलेस’ का पुनर्निर्माण कराएगा चीन

दलाई लामा के ‘पोटाला पैलेस’ का चीन पुनर्निर्माण कराएगा। यूनेस्को ने महल को वैश्विक धरोहरों में शामिल कर रखा है। चीन की सरकारी न्यूज एंजेंसी का कहना है कि इसके सौंदर्यीकरण पर लगभग 15 लाख डॉलर का खर्च आएगा। महल को 45 वर्ष की अथक मेहनत के बाद 1694 में पूरा किया जा सका था। 13 मंजिल के भवन में एक हजार से ज्यादा कमरे हैं। इसमें लगभग दो लाख मूर्तियां व दस हजार मठ स्थित हैं। इसके निर्माण में भूकंपरोधी तरीकों का इस्तेमाल खासतौर पर किया गया है। तिब्बत-चीन संघर्ष के दौरान महल को काफी क्षति पहुंची थी।

#### क्या है

1. 1959 तक यह आस्था का प्रमुख केंद्र रहा, लेकिन चीन से लड़ाई के दौरान 14 वें दलाई लामा तेनजिन ग्यास्टो भारत आ गए। उसके बाद से ये महल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
2. पिछले साल एक करोड़ 37 लाख पर्यटक यहां पर दर्ज किए गए थे। लेकिन अब यहां पर रोजाना 16 सौ पर्यटक ही जा सकते हैं।
3. संकरे गलियारों व कमरों में ज्यादा भीड़ का होना नुकसानदेह है। चीन की सरकारी न्यूज एंजेंसी का कहना है कि इसके सौंदर्यीकरण में स्वर्ण जड़ित छतों की आभा को फिर से बहाल करने का काम होगा।
4. सर्विलांस सिस्टम को भी दोबारा तैयार किया जाएगा। महल के प्रशासकीय तंत्र से जुड़े अधिकारी जार्डन का कहना है कि छतों पर लगी सोने की प्लेट तेज हवा, बारिश व सूर्ज की रोशनी से खराब हो चुकी है। दोबारा मरम्मत से इसे नया जीवन मिलेगा।
5. यूनेस्को ने इसे 1994 में अपनी वैश्विक धरोहरों में शामिल किया था। अब इसे संग्रहालय में तब्दील करके पर्यटक के लिए खोला गया है। ये तिब्बत का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।

#### WHO में भारत

भारतीय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का डिप्टी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। स्वामीनाथ डब्लूएचओ में इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय हैं। उनका जिम्मा संगठन के कार्यक्रमों पर नजर रखने का होगा। डब्लूएचओ की ओर से ट्रीट कर उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। डब्लूएचओ के डायरेक्टर ट्रेडोस अधनोम गेब्रेयेसस ने अपनी सीनियर लीडरशिप टीम के बारे में जानकारी दी थी और उनकी टीम में सौम्या को जगह मिली है।

#### क्या है

1. जिस टीम में सौम्या को जगह मिली है उसमें 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें डब्लूएचओ के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं।

#### कौन हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन?

1. डॉक्टर सौम्या कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं।
2. एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
3. सौम्या ने अपनी एकेडमिक ट्रेनिंग भारत, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और अमेरिका में पूरी की है।
4. सौम्या वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) में डायरेक्टर जनरल हैं।
5. सौम्या देश की मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनके पास विलनिकल केयर और रिसर्च में 30 साल का अनुभव है।
6. सौम्या को खास तौर पर टीबी पर की गई उनकी रिसर्च के लिए जाना जाता है।
7. अपनी रिसर्च की मदद से उन्होंने कई प्रभावी कार्यक्रम तैयार किए हैं।
8. सौम्या साल 2009 से 2011 तक यूनिसेफ के लिए को-ऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं।
9. इस दौरान उन्होंने जेनेवा में ट्रॉपिकल बीमारियों के क्षेत्र में काम किया।
10. ट्रॉपिकल बीमारियां मच्छर जनित इलाकों में होती हैं।
11. वह डब्लूएचओ और ग्लोबल एडवाइजरी बॉडी का हिस्सा भी रही हैं।

2. सीनियर लीडरशीप टीम में 60% महिलाएं हैं। डॉक्टर गेब्रेयेसस ने अपनी नई टीम के बारे में जानकारी देने के बाद कहा, 'मेरा मानना है कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए शीर्ष प्रतिभा, लिंग समानता और भौगोलिक विविधता की जरूरत होती है। इस मक्सद को पूरा करने के लिए ये एक मजबूत टीम है।'

## US ने CPEC और OBOR का किया विरोध

CPEC को लेकर पहली बार अमेरिका ने भारत के दावों का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। अमेरिका का कहना है कि यह प्रोजेक्ट एक विवादित इलाके में बन रहा है। अमेरिका ने पहली बार कांग्रेस को इस बात की जानकारी दी है कि वह मानता है कि चीन-पाकिस्तान के बीच बनने वाला आर्थिक गलियारा उस विवादित इलाके से गुजरता है जिस पर भारत अपना दावा करता आया है। इसके अलावा अमेरिका ने ओबीओआर को लेकर भी ऐसी ही टिप्पणी की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने यहां तक कहा कि वह मानते हैं यहां पर जबरन इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। उन्होंने सीधेतौर पर कहा कि अमेरिका चीन ओबीओआर प्रोजेक्ट का विरोध करता है, क्योंकि मौजूदा समय में कई रोड हैं और कई बेल्ट भी हैं। मैटिस का कहना था कि अमेरिका इसलिए भी इसका विरोध करता है क्योंकि यह विवादित इलाके से होकर गुजरता है।

### क्या है

1. अमेरिका की तरफ से सामने आए पहले बड़े बयान के भारत के लिए काफी मायने हैं। यह इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि भारत कई मंचों पर इस बात को दुनिया को बताता रहा है कि जिस इलाके में चीन-पाकिस्तान के बीच आर्थिक गलियारा बन रहा है वह कानून भारतीय क्षेत्र में आता है जिस पर पाकिस्तान ने वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
2. लेकिन अब अमेरिका के इस बाबत सामने आए बयान के बाद भारत के इन्हीं दावों को बल मिला है। वहीं दूसरी तरफ इस बयान से दुनिया में एक मैसेज यह भी गया है कि भारत का कथन और दावा इस बाबत पूरी तरह से सही है।
3. ऑब्जरवर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत भी मानते हैं कि अमेरिका ने आर्थिक गलियारे पर इस तरह का बड़ा बयान पहली बार दिया है। यह उनके द्वारा भारत के दावों को भी सही ठहराता है।
4. इसका असर आने वाले समय में भी जरूर दिखाई देगा। उनका कहना है कि 56 बिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी समय से सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका के इस बयान के बाद वह देश जो अमेरिका के सहयोगी है और जो इस आर्थिक गलियारे को सही मानते हैं या इसमें सहभागी है, इस पर एक बार दोबारा विचार जरूर करेंगे।
5. अमेरिका के इस बयान के मायने के रूप में जहां प्रोफेसर पंत भारत के दावों को सही ठहराना मानते हैं वहीं वह यह भी मानते हैं कि हाल के कुछ समय में जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं, अमेरिका के बयान से यह बात साबित होती है।
6. प्रोफेसर पंत का यह भी कहना है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर पाकिस्तान में ही काफी विरोध है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर ग्वादर तक में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग यह बात मानते हैं कि इससे पाकिस्तान को न के बराबर फायदा है जबकि चीन को इससे बेतहाशा फायदा होगा। इन विरोधों के बीच चीन के लिए यह प्रोजेक्ट सफल तरीके से पूरा करना एक बड़ी चुनौती है।

## UNESCO से बाहर होगा अमेरिका

अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की। उसने संयुक्त राष्ट्र की इस सांस्कृतिक संस्था पर इस्माइल विरोधी रूख अपनाने का आरोप लगाया है। पेरिस स्थित यूनेस्को ने 1946 में काम करना शुरू किया था और यह विश्व धरोहर स्थल को नामित करने को लेकर मुख्य रूप से जाना जाता है।

### क्या है

1. यूनेस्को से बाहर होने का अमेरिका का फैसला 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी होगा। हालांकि, अमेरिका उस वक्त तक यूनेस्को का एक पूर्णकालिक सदस्य बना रहेगा।
2. यह फैसला यूनेस्को पर बढ़ती बकाया रकम की चिंता और यूनेस्को में इमाइल के खिलाफ बढ़ते पूर्वार्थ को जाहिर करता है। संस्था में मूलभूत बदलाव करने की जरूरत है।
3. विदेश विभाग ने संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) महानिदेशक इरीना बोकोवा को संस्था से अमेरिका के बाहर होने के फैसले की सूचना दी और यूनेस्को में एक स्थायी पर्यवेक्षक मिशन स्थापित करने की मांग की है।
4. अमेरिका ने महानिदेशक को गैर सदस्य पर्यवेक्षक के तौर पर यूनेस्को के साथ जुड़े रहने की अपनी इच्छा जाहिर की है ताकि संगठन द्वारा उठाए जाने वाले कुछ अहम मुद्दों पर अमेरिकी विचार, परिप्रेक्ष्य और विशेषज्ञता में योगदान दिया जा सके।
5. इन मुद्दों में विश्व धरोहर की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता की हिमायत करना और वैज्ञानिक सहयोग एवं शिक्षा को बढ़ावा देना भी शामिल है।

### चीन ने वापस ली यूनेस्को प्रमुख की दावेदारी

चीन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के प्रमुख पद की दावेदारी छोड़ दी है। उसने मिस्र के उम्मीदवार के समर्थन में अपने उम्मीदवार को हटा लिया है। इससे पहले ही इजरायल और अमेरिका ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस संगठन से अलग होने की घोषणा की है।

### क्या है

1. चीन ने कहा कि चीन इस बात का समर्थन करता है कि यूनेस्को अपने नियमों के अनुसार एक योग्य तथा सभी सदस्य देशों की अकांक्षाओं को पूरा करने वाले महानिदेशक का चयन करे। उन्होंने यह बताने से इनकार किया कि चीन ने कियान तांग की उम्मीदवारी क्यों वापस ली है।
2. चीन आशा करता है कि सभी देश इस संदर्भ में योगदान देंगे और बीजिंग यूनेस्को में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा।
3. इस बीच, मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद अबू जैद ने बताया कि चीन ने उनके प्रत्याशी के समर्थन में यूनेस्को की अपनी उम्मीदवारी वापस ली है।

### श्रीलंका में अब भारत बनाएगा एयरपोर्ट

श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत हम्बनटोटा के निकट मट्टाला एयरपोर्ट को विकसित करने को तैयार हो गया है। इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। यह जानकारी स्वयं श्रीलंका के नागरिक विमानन मंत्री निमल श्रीपाला ने हाल में दी। बता दें कि 'बेल्ट एंड रोड पहल' के तहत चीन ने इस इलाके में भारी निवेश किया है। श्रीलंका हम्बनटोटा इलाके में निवेश के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस इलाके में चीन ने बंदरगाह का निर्माण किया है और निवेश क्षेत्र और तेल शोधन कारखाना लगाने पर चर्चा की जा रही है।

### क्या है

1. भारत एक प्रस्ताव के साथ सामने आया है। नई दिल्ली हवाई अड्डे और एविएशन सर्विसेज लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने को तैयार है। बता दें कि श्रीलंका की सरकारी कंपनी एविएशन सर्विसेज कोलंबो और दक्षिण के मट्टाला हवाई अड्डे का परिचालन करती है।
2. भारत ने घाटे में चल रहे मट्टाला हवाई अड्डे के विस्तार और प्रबंधन के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने का प्रस्ताव किया है। यह हवाई अड्डा हम्बनटोटा के करीब है।

3. नई दिल्ली श्रीलंका को हिस्सेदारी और निवेश के स्वरूप को तय करने की छूट देगा। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इसपर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
4. श्रीलंकाई कैबिनेट नोट के मुताबिक शुरुआत में योजना के तहत 29.3 करोड़ डॉलर (करीब 1900 करोड़ रुपये) का निवेश होगा। इसमें भारत 70 फीसदी राशि 40 साल के लिए लीज पर देगा।
5. चीन ने मट्टाला हवाई अड्डे का निर्माण 25.3 करोड़ डॉलर (करीब 1600 करोड़ रुपये) की लागत से किया है। इसके लिए चीन ने ही 23 करोड़ डॉलर का कोष उपलब्ध कराया है।
6. इस हवाई अड्डे से रोजाना दुबई के लिए केवल एक विमान का परिचालन होता है और यह दुनिया के सबसे खाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में बदनाम है।
7. श्रीलंका की पिछली सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया है। चीन की मंशा इस इलाके में विस्तार करना है। वह यहां तेलशोधन कारखाना लगाना चाहता है।
8. श्रीलंका भी इसे निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके लिए छह हजार हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग पर मौजूद है और यूरोप और एशिया के भारत शुरू से ही चीन की पड़ोसी देशों में भारी-भरकम निवेश को शंका की नजर से देखता है। लेकिन 2014 में चीन ने नई दिल्ली की शंका को पुष्ट करते हुए कोलबों बंदरगाह पर अपनी पनडुब्बी खड़ी कर दी।
9. इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं हरकत में आया और प्रभाव को बहाल करने की रणनीति बनाई।

## अर्थशास्त्र

### भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम 2016 प्रभावी

12 अक्टूबर, 2017 से भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम 2016 प्रभावी हो गया है। यह अधिनियम 22 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय मानक परिषद (बीआईएस) को भारत का राष्ट्रीय मानक अंग के रूप में स्थापित करता है।

क्या है

1. इस अधिनियम के तहत सूचिबद्ध उद्योग की किसी वस्तु या विषय, कोई प्रक्रिया, प्रबन्ध या सेवा जिसे सरकार जनहित में आवश्यक समझती है या मानव, पशु या वृक्ष हित व सुरक्षा के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या अनुचित व्यापारिक कार्यप्रणाली के बचाव व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये सरकार को अनिवार्य प्रमाणीकरण शासन पद्धति के अन्तर्गत लाने के प्रावधान के लिये सक्षम बनाती है।
2. सक्षमता का यह प्रावधान बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉल मार्किंग की अनिवार्यता के लिये भी बनाया गया है।
3. यह नया अधिनियम विभिन्न सरलीकृत अनुपालन मूल्यांकन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार को उत्पादों एवं सेवाओं के मानक और अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के लिये, बीआईएस के अलावा, किसी प्राधिकरण या एजेन्सी को नियुक्त करने के लिए सक्षम बनाती है।
4. यह नया अधिनियम देश में व्यापार करने में सरलता प्रदान करेगा और मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहित करेगा तथा ग्राहकों के लिये गुणवत्ता उत्पाद एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

### भारत में पहली अमेरिकी क्रूड की खेप

भारत में पहली बार अमेरिकी कच्चे तेल की खेप 2 अक्टूबर को पहुंची। यह खेप ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर वेरी लार्ज क्रूड कैरियर (वीएलसीसी) के जरिये पहुंची। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने जुलाई में अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद की थी। इसके साथ अमेरिकी कच्चे तेल की भारी सप्लाई भारत में शुरू होने का रास्ता खुल गया है।

### क्या है

1. आइओसी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) भी अमेरिकी कच्चा तेल आयात करने का प्रयास कर रही है।
2. आइओसी के चेयरमैन संजीव सिंह के अनुसार लाख बैरल (प्रति बैरल 158 लीटर) अमेरिकी कच्चे तेल का पोत पारादीप बंदरगाह पर पहुंची।
3. केंद्र सरकार अमेरिका और कनाडा का कच्चा तेल अमेरिकी तटों से खरीदने के लिए सार्वजनिक कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि सरकार इसे सस्ते विकल्प के तौर पर देखती है। अमेरिकी कच्चे तेल की वजह से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति मांग से ज्यादा हो गई है।
4. आइओसी और बीपीसीएल ने मार्च 2018 तक कच्चे तेल के आठ पोत खरीदने की प्रतिबन्धता जताई है।
5. दूसरी खेप में वह 19 लाख बैरल अमेरिका कच्चा तेल खरीदेगी। इसमें से करीब आधा शेल ऑयल होगा। शेल ऑयल भी कच्चा तेल ही होता है। यह किसी तेल कुएं के बजाय जमीन के अंदर चट्टानों के बीच एकत्रित भंडारों से निकाला जाता है। आइओसी ने 9.50 लाख बैरल लाइट स्वीट ईंगल फोर्ड शेल ऑयल और इतना ही हैवी सोर मार्स क्रूड आयात होगा।
6. दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत दक्षिण कोरिया, जापान और चीन की तरह अमेरिकी कच्चा तेल खरीदने लगा है।
7. तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी किये जाने के बाद मध्य पूर्व में हैवी सोर क्रूड यानी हाई सल्फर क्रूड की कीमत बढ़ने लगी है।

### जीएसटी काउंसिल 22वीं बैठक

जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें कंपोजीशन स्कीम की लिमिट बढ़ाना, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को मासिक के बजाए तिमाही आधार पर भरना अनिवार्य करना और कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरों को कम करना प्रमुखता से शामिल है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि काउंसिल के फैसले के बाद क्या कुछ सस्ता होने जा रहा है।

### जाने क्या कुछ होगा सस्ता:

1. आम, खाखरा और आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी की दर को 12 फीसद से कम कर 5 फीसद कर दिया गया है।
2. स्टेशनरी के कई सामान पर लगने वाली जीएसटी की 28 फीसद दर को घटाकर 18 फीसद कर दिया गया है।
3. हाथ से बने धागों पर जीएसटी की दर 18 फीसद से कम कर 12 फीसद कर दी गई है।
4. अब प्लेन चपाती पर लगने वाली जीएसटी की दर 12 फीसद नहीं बल्कि 5 फीसद होगी।
5. साथ ही आईसीडीएस किड्स फूड पैकेट पर जीएसटी की दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है।
6. अनब्रैंडेड नमकीन पर अब 5 फीसद की जीएसटी लगेगी।
7. अनब्रैंडेड आयुर्वेदिक दवाओं पर भी 5 फीसद की जीएसटी लागू होगी।
8. डीजल इंजन के पार्ट्स पर अब 18 फीसद की दर से जीएसटी लगेगी।
9. दरी (कारपेट) पर जीएसटी की दर को 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है।
10. प्लास्टिक वेस्ट और रबर वेस्ट पर अब 18 से बजाए 5 फीसद की दर से जीएसटी देना होगा। वहीं पेपर वेस्ट पर 12 के बजाए 5 फीसद जीएसटी देना होगा।
11. मैन मेड यार्ड पर अब 12 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा।

## जनधन खाते से महंगाई पर असर

सरकार की ओर से शुरू की गई जनधन योजना के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जनधन खाते की सबसे अधिक संख्या है, उन राज्यों में ग्रामीण मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर आ गई है। यह जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट ईकोरैप में सामने आई है। साथ ही देशभर में बीते वर्ष नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में इजाफा देखने को मिला है। अबतक देश में 30 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

### क्या है

1. रिपोर्ट में बताया गया है कि जनधन खाते वाले टॉप 10 राज्यों में लगभग 23 करोड़ खाते खोले गए हैं। यह कुल जनधन खातों का 75 फीसद है। देशभर में इन खातों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है।
2. यूपी में 4.7 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसके बाद अगले पायदान पर बिहार है, जहां 3.2 करोड़ खाते हैं। वहाँ, तीसरे पर पश्चिम बंगाल है जहां 2.9 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।
3. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 फीसद जनधन खाते सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही खुले हैं। वहाँ, देश के जिन राज्यों में यह खाते सबसे ज्यादा खुले हैं, वहाँ ग्रामीण मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर है। इससे पता चलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप ले चुकी है।
4. उल्लेखनीय है कि जनधन योजना को इस साल अगस्त में तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए इस योजना को ऐतिहासिक पहल बताया था।
5. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 23 सिंतबर को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा के 72वें सत्र में संबोधन देते हुए जनधन योजना की सरहाना की थी।

## भारत के लिए आईएमएफ ने दिए तीन अहम सुझाव

आईएमएफ ने भारत में संरचनात्मक सुधारों के लिए एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है जिसमें श्रम कानूनों की संख्या में कमी लाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और लिंगभेद को खत्म करना प्रमुखता से शामिल है। एशिया पैसिफिक विभाग के उप-निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) केनेथ कांग ने बताया, “एशिया का परिदृश्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के साथ भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है। ढांचागत सुधारों के मामले में तीन नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।”

### क्या है

1. पहली प्राथमिकता कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की हालत को सुधारना है। इसके लिए गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के समाधान को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी आधिक्य का पुनर्निर्माण और बैंकों की ऋण वसूली प्रणाली को बेहतर बनाना होगा।
2. दूसरी प्राथमिकता में भारत को राजस्व संबंधी कदम उठाकर अपने राजकोषीय एकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। साथ ही सब्सिडी के बोझ को भी कम करना चाहिए।
3. भारत को तीसरी प्राथमिकता के मुताबिक बुनियादी ढांचा अंतर को पाटने के लिए ढांचागत सुधारों की गति बनाए रखना और श्रम एवं उत्पाद बाजार की क्षमता का विस्तार होना चाहिए। साथ ही कृषि सुधारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए।
4. इसके अलावा श्रम बाजार सुधारों के लिए निवेश और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए मार्केट रेग्युलेशन में सुधार किए जाने चाहिए। साथ ही श्रम कानूनों की संख्या घटायी जानी चाहिए जो अभी केंद्र और राज्य के स्तर पर कुल मिलाकर करीब 250 हैं।

## वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार अभी अधूरा

वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की संचालन समिति ने इसके प्रति आगाह किया है। आईएमएफ ने नीति निर्माताओं को चेताया है कि मध्यम अवधि के आर्थिक जोखियों तथा बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से वे आत्ममुअध न हों और सतर्कता बरतें।

**क्या है**

1. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और वित्त समिति (आईएमएफसी) ने जारी वक्तव्य में कहा कि निवेश, व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात में सुधार अभी पूरा नहीं हुआ है। ज्यादातर विकसित देशों में मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है। कई देशों में वृद्धि की संभावनाएं कमज़ोर हैं।
2. निकट भविष्य के जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं, लेकिन मध्यम अवधि के जोखियों को देखते हुए किसी तरह आत्मसंतुष्ट होने की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव भी एक जोखिम है। समिति ने नीति निर्माताओं से कहा है कि वे अनुकूल मौद्रिक नीतियां अपनाएं। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां लचीली और वृद्धि अनुकूल होनी चाहिए।
3. इसके अलावा समिति ने विनिमय दरों में अत्यधिक उत्तर-चढ़ाव के प्रति भी आगाह किया है। समिति का कहना है कि इससे आर्थिक स्थिरता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

## विज्ञान एवं तकनीकी

### पृथ्वी के निकट से सुरक्षित गुजर गया क्षुद्र ग्रह

पृथ्वी के निकट आ रहा 2012 टीसी 4 क्षुद्र ग्रह आखिरकार बगेर किसी नुकसान के गुजर गया। इसके पृथ्वी के निकट आने से खतरे की आशंका व्यक्त की जा रही थी। हालांकि वैज्ञानिक इसको पहले ही खारिज कर चुके थे। यही नहीं वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि आने वाले 100 साल तक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। 2012 में हवाई द्वीप में खगोल वैज्ञानिकों ने इस क्षुद्र ग्रह को पहली बार देखा था, जोकि पृथ्वी से 94 हजार 800 किमी दूर था। इस बार इसकी दूरी 6 हजार 800 किमी तक रहने की संभावना थी। इसके चलते इससे अधिक खतरा बताया जा रहा था। हालांकि पृथ्वी से इसकी दूरी के इस बार के अधिकृत आंकड़े सामने आने अभी बाकी हैं।

**क्या है क्षुद्र ग्रह:**

1. हमारे सौर मंडल की संरचना एक तारे के टूटने से बताई जाती है। इसमें अधिक द्रव्यमान से सूरज बना, वहीं शेष मॉलीक्यूलर क्लाउड से पृथ्वी सहित अन्य गृह बने। लेकिन इस दौरान बड़ी तादाद में मैटीरियल गृह का आकार नहीं ले सका और यह मैटीरियल क्षुद्र ग्रह के रूप में सौर मंडल में मौजूद रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल व बृहस्पति के बीच ये मौजूद हैं। कई बार सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के निकट भी आ जाते हैं।
2. पृथ्वी पर टकराने से बना चंद्रमा: खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का निर्माण भी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। यहीं नहीं 6.5 करोड़ साल पहले क्षुद्र ग्रह ने ही पृथ्वी से डायनासोर का अस्तित्व खत्म किया था। यही नहीं महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण भी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण होना बताया जाता है।

### अल नीनो से कार्बन डाईऑक्साइड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक अध्ययन के मुताबिक साल 2015-16 में लबे समय तक चले अल नीनो की वजह से बड़े पैमाने पर वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड में बढ़ोतरी हुई है। नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी-2 (-2) उपग्रह से मिले पहले 28 महीने के आंकड़ों के विश्लेषण से रिसर्चर्स इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अल नीनो से संबंधित ताप और सूखा वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहा।

### क्या है

1. अल नीनो समुद्र के उस गर्म जल को कहा जाता है जिसका विकास प्रशांत महासागर में होता है और यह विश्वभर में तापमान और बारिश में बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है।
2. साल 2015-16 का अलनीनो काफी लंबा था और वैज्ञानिकों को संदेह है कि यह बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार था।
3. हालांकि, वैज्ञानिकों को अभी यह पता नहीं चला है कि यह कैसे हुआ। यह अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। अमेरिका में नासा की जेट प्रक्षेपण प्रयोगशाला और इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाली जूनजी ल्यू ने कहा, इन तीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ने साल 2011 के मुकाबले वातावरण में 2.5 गीगा टन अधिक कार्बन उत्सर्जन किया।

## विविध

### मुख्यालय समन्वित रक्षा स्टाफ का स्थापना दिवस

मुख्यालय समन्वित रक्षा स्टाफ ने 1 अक्टूबर को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इस स्मारक दिवस के अवसर पर आईडीएस के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन (सीआईएससी) लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सशस्त्र सेनाओं के पराक्रमी शहीदों को पुष्टांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आईडीएस के सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

### क्या है

1. इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने प्रतिबद्धता और निष्पार्थ सेवा के लिए आईडीएस के सभी रेंकों के जवानों और अधिकारियों की सराहना की और उनका आहवान किया कि वे व्यवसायिक प्रतिबद्धता के उच्च मानदंडों को बनाए रखें और आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करते रहें।
2. सरकार ने अक्टूबर 2001 में 'ऑपरेशन विजय' (कारगिल ऑपरेशन) के दौरान हेडक्वार्टर आईडीएस का गठन किया था।
3. इसका प्रमुख उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच सदृश्यता को बढ़ावा देने और रक्षा मंत्रालय के साथ इनके समन्वय के लिए किया था। आईडीएस का सर्वोच्च लक्ष्य 'एकता के बल पर विजय हासिल करना' है। आईडीएस ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस भावना के बल पर महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित किए हैं।

### नवबौद्धों को अल्पसंख्यक का दर्जा

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नवबौद्ध समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया है। इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। अब नवबौद्ध समाज को अल्पसंख्यकों को मिलने वाले सभी लाभ और सुविधाएं मिलेंगी।

### क्या है

1. महाराष्ट्र में भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर के अनुयायियों को नवबौद्ध कहा जाता है।
2. बाबासाहेब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में धर्मांतर कर अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था।
3. महाराष्ट्र सरकार ने बाबासाहेब आंबेडकर के अनुयायियों को नवबौद्ध के रूप में अधिसूचित किया है। तब से उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जा रही है। इसलिए महाराष्ट्र के नवबौद्धों को कानूनन बौद्ध माना जाता है।
4. इस प्रकार उन्हें बौद्ध अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होता है और अल्पसंख्यक समाज के लिए संचालित सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पाने के लिए वे कानूनी रूप से पात्र हैं।
5. महाराष्ट्र में अब तक मुस्लिम, इसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा है। अब इसमें नवबौद्ध समुदाय का समावेश किया गया है।

## प्रथम बार महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना

राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति की समाधि, राजघाट को पहली बार एक नयी विशेषता हासिल की है जो भारी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती है। भारत के उपराष्ट्रपति एम. वैंकेया नायडू ने 2 अक्टूबर को तंत्र भारत के शूरवीर की 148वीं जन्मशताब्दी पर महात्मा गांधी की 1.80 लम्बी कांस्य प्रतिमा अनावरण किया। श्री राम सुतार द्वारा तराशी गई प्रतिमा को राजघाट समाधि परिसर के पार्किंग क्षेत्र में 8.73 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। यह 2 फीट ऊँचे मूर्तितल पर ग्रेनाइट धातु में लिपटा हुआ है। मूर्तितल के सामने की दिशा में गांधी जी का प्रसिद्ध संदेश “जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, वही बनो” को उत्कीर्ण किया गया है। प्रतिमा को स्थापित करना, गत तीन वर्षों में राजघाट में किए गए बहुसंख्य सुधार कार्यों का हिस्सा है।

### क्या है

- प्रतिदिन 10 हजार लोग राजघाट आते हैं और विदेशी मान्यगण, सादे काले रंग के पत्थर के चबूतरे पर जहाँ गांधी जी का दाह संस्कार किया गया था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह नई प्रतिमा उस महान आत्मा को सम्मान देने के लिए एक अन्य स्थान प्रदान करेगी।
- इस समाधि परिसर को नया प्रशासनिक खण्ड मिला है जो आगंतुक कक्ष, प्रकाशन इकाई, स्टाफ कक्ष, पेयजल सुविधा से सुसज्जित है।
- इसका निर्माण लगभग 75 लाख रुपये की लागत से किया गया है।
- पिछले तीन वर्ष के दौरान आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और राजघाट समीति ने राजघाट पर आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यों को शुरू करने का दायित्व लिया है।

## बंदूकों का लाइसेंस रखने वाले राज्यों की सूची

उत्तर प्रदेश में 12.77 लाख लोगों के पास हथियार रखने का लाइसेंस है और यह राज्य बंदूकों के लाइसेंसों वाले प्रांतों की सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे स्थान पर है आतंकवाद प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार, देश में बंदूकों के जारी लाइसेंस की संख्या 33,69,444 है। बंदूक रखने के सर्वाधिक लाइसेंस उत्तर प्रदेश में है जहां पर 12,77,914 लोग हथियार रख सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने निजी सुरक्षा के नाम पर लाइसेंस लिये हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है।

### क्या है

- मंत्रालय ने बताया कि करीब तीन दशक से आतंकवाद से पीड़ित जम्मू कश्मीर में 3,69,191 लोगों के पास बंदूक के लाइसेंस हैं। इसमें प्रतिबंधित बोर और गैर प्रतिबंधित बोर, दोनों ही तरह के हथियार शामिल हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, प्रांत की कुल आबादी 1,25,41,302 है।
- 1980 और 90 के दशक में आतंकवाद से पीड़ित रहे पंजाब में बंदूक के लाइसेंस की संख्या 3,59,349 है। इनमें से ज्यादातर लाइसेंस राज्य में आतंकवाद के दो दशकों के दौरान जारी किये गये थे। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, पंजाब की कुल आबादी 2,77,43,338 है।
- इसमें बताया गया है कि इसके बाद मध्य प्रदेश में 2,47,130 और हरियाणा में 1,41,926 लोगों के पास बंदूक रखने का लाइसेंस है। अन्य राज्यों में राजस्थान में (1,33,968 लाइसेंस), कर्नाटक (1,13,631), महाराष्ट्र (84,050), बिहार (82,585), हिमाचल प्रदेश (77,069), उत्तराखण्ड (64,770), गुजरात (60,784) और पश्चिम बंगाल (60,525) हैं।
- आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में लाइसेंसशुदा बंदूकधारियों की संख्या 38,754 है जबकि नगालैंड में 36,606, अस्सीचल प्रदेश में 34,394, मणिपुर में 26,836, तमिलनाडु में 22,532 और ओडिशा में 20,588 लाइसेंस जारी किये गये हैं।

5. मंत्रालय के मुताबिक, सबसे कम लाइसेंस केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली में जारी किये गये। इन प्रदेशों में केवल 125-125 लाइसेंस जारी किए गए।

### अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला चिकित्सा का नोबेल

दुनिया के प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कारों की घोषणा 2 अक्टूबर को हो गई है। तीन अमेरिकी वैज्ञानिक जेफरी सी हॉल, माइकल रोजबस और माइकल डब्ल्यू यंग को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को आंतरिक जैविक विषय पर किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राइज के लिए चुना गया। आंतरिक जैविक गुण को सर्केंडियन रिदम के नाम से जाना जाता है।

**क्या है**

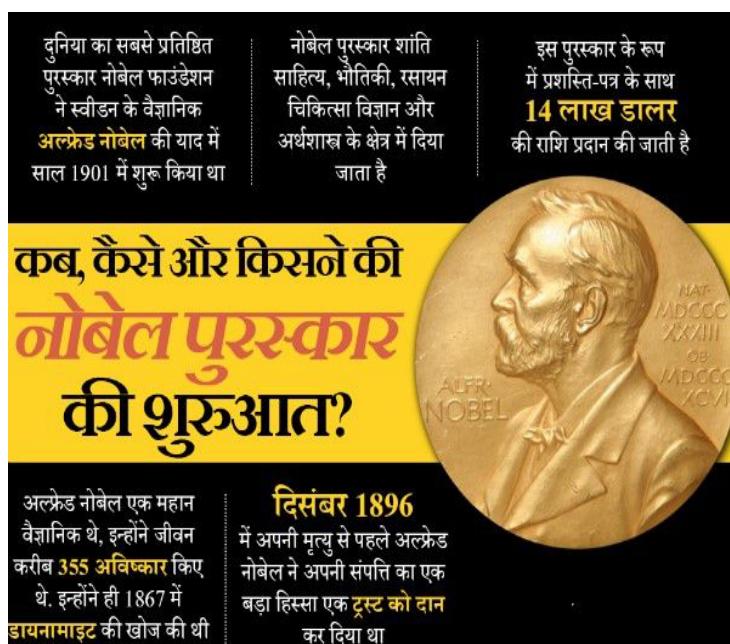
1. नोबेल असेंबली ने कहा है, उनकी खोजों में इस बात की व्याख्या की गई है कि पौथे, जानवर और इंसान किस प्रकार अपनी आंतरिक जैविक गुण के अनुरूप खुद को ढालते हैं ताकि वे धरती की परिक्रमा के अनुसार अपने को ढाल सकें।
2. स्टॉकहोम के कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट में नोबल पुरस्कार समिति इस सीजन की शुरुआत मेडिसिन फील्ड में नोबल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति के नाम की घोषणा के साथ की।

### भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2017

अमेरिकी खगोलविज्ञानियों बैरी बैरिश, किप थोर्ने और रेनर वेस को गुरत्व तरंगों की खोज के लिए इस साल का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। उनकी यह खोज गहन ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। अलबर्ट आइंस्टीन ने करीब एक सदी पहले अपनी सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के तहत गुरत्व तरंगों का अनुमान लगाया था लेकिन 2015 में ही इस बात का पता लगा कि ये तरंगे अंतरिक्ष-समय में विद्यमान हैं।

**क्या है**

1. ब्लैक होल के टकराने या तारों के केंद्र के विखंडन से यह प्रक्रिया होती है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने वाली स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रमुख जी के हनसॉन ने कहा, उनकी खोज ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने सितंबर 2015 में यह खोज की थी और फरवरी 2016 में इसकी घोषणा की थी।
2. दशकों के वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद यह ऐतिहासिक खोज हुई है। तभी से तीनों वैज्ञानिक खगोलशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाले सभी बड़े पुरस्कार अपने नाम करते आ रहे हैं। थोर्ने और वेस ने प्रतिष्ठित कैलिफॉर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संयुक्त रूप से लेजर इंटरफियरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेब ऑब्जर्वेटरी (लीगो) बनाया था।
3. इसके बाद बैरिश ने परियोजना को अंतिम रूप प्रदान किया। करीब 1.3 अरब प्रकाशवर्ष दूर हुए घटनाक्रम के परिणामस्वरूप पहली बार गुरत्व तरंगों का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला था।



4. अकादमी ने कहा, पृथ्वी पर जब सिग्नल पहुंचा तो बहुत कमज़ोर था लेकिन खगोलविज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। गुरत्व तरंगें अंतरिक्ष में सबसे प्रचंड घटनाक्रमों पर नजर रखने और हमारे ज्ञान की सीमाओं को परखने का पूरी तरह नया तरीका हैं। ब्लैक होल से कोई प्रकाश नहीं निकलता इसलिए उनका पता केवल गुरत्व तरंगों से चल सकता है।
5. इस साल के नोबेल पुरस्कारों में सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा की गई और दूसरे स्थान पर भौतिकी के विजेताओं का नाम घोषित किया गया है। 4 अक्टूबर को रसायनविज्ञान के विजेताओं के नाम की घोषणा होगी।

### **रसायन का नोबेल पुरस्कार 2017**

द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने 4 अक्टूबर को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की। जैक्स ड्यूबिचित, जोएचिम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को बॉयोमालीक्यूल्स के सॉल्यूशन के उच्च संकल्प संरचना के निर्धारण के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने को लेकर सम्मानित किया गया। जैक्स ड्यूबिचित स्विजरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लूसियाना में कार्यरत हैं। फ्रैंक न्यूयार्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ रिचर्ड हेंडरसन कैंब्रिज की एमआरसी लैबोरेटरी ऑफ मॉलीक्यूलर बॉयोलोजी में सेवारत हैं।

#### **क्या है**

1. रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1901 से 2016 के बीच 108 बार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गयी। अब तक कुल 174 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
2. इस वर्ग में 63 वैज्ञानिकों को एकल तौर पर पुरस्कार दिया गया है। बाकी वैज्ञानिकों को संयुक्त तौर पर पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अब तक कुल चार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फेडरिक सेंगर एक मात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं, जिन्हें दो बार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें वर्ष 1958 और 1980 में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
3. रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक फेडरिक जिलोट थे, जिन्हें वर्ष 1935 में 35 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
4. वहाँ सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक जॉन बी फेन रहे, जिन्हें 85 वर्ष की आयु में वर्ष 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों की औसत आयु 58 वर्ष रही है।

### **साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017**

वर्ष 2017 के नोबेल पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को नवाजा गया। काजुओ इशिगुरो को उनके नॉवेल (उपन्यास) 'ग्रेट इमोशनल फोर्म' के लिए दिया गया। इशिगुरो का यह नॉवेल दुनिया के साथ जुड़ाव के हमारे भ्रामक अर्थों का खुलासा करता है।

#### **क्या है**

1. काजुओ इशिगुरो का जन्म जापान में 8 नवम्बर 1954 को हुआ था। पांच साल की उम्र में उनका परिवार ब्रिटेन में आकर बस गया था।
2. साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1901 से 2016 तक कुल 109 नोबेल पुरस्कार दिये गये हैं, इसमें से 14 बार महिलाओं को साहित्य के पुरस्कार से नवाजा गया है। चार नोबेल पुरस्कार को दो लोगों में बांटा गया है।
3. सबसे कम उम्र में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 41 वर्षीय रुद्रयार्ड किपलिंग हैं। किपलिंग को उनके उपन्यास जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

4. साहित्य के क्षेत्र में सबसे उम्रदाराज साहित्यकार 88 वर्षीय डोरिस लेसिंग थीं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें वर्ष 2007 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले साहित्यकारों की औसत उम्र 65 वर्ष है।

## शांति नोबेल पुरस्कार 2017

शांति के नोबेल पुरस्कार 2017 का ऐलान हो गया है। इस साल एंटी न्यूक्लियर अभियान चलाने वाली संस्था आईसीएएन (ICAN) को ये सम्मान मिला है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के मुताबिक, आईसीएएन को 2017 का शांति के नोबेल पुरस्कार दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद भयावह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उसके प्रयासों की वजह से दिया गया है। कमेटी ने पुरस्कार की घोषणा के समय कहा कि हम इसके जरिए सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह कितना विनाशकारी साबित हो सकता है।

**शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है**

1. शांति का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो दो देशों के बीच भाई-चारे को बढ़ावा देते हैं या फिर समाज के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं जिससे लोगों को नई जिंदगी मिलती है। भारत में मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को शांति पुरस्कार दिया जा चुका है जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अहम योगदान दिया। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है।
2. शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में जबकि अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं।

### कैसे दिए जाते हैं

1. इस साल दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार में पदक के साथ लगभग 5.35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अक्टूबर में रॉयल अकाडेमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के विजेताओं का नाम तय करती है।
2. नाम तय करने की प्रक्रिया में पहले कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है और उन पर कमिटी के सदस्य वोट करते हैं।
3. जानकारी के मुताबिक इमारत में एक स्टेज होता है जहां एक बॉक्स रखा जाता है और हर सदस्य वहां ऊपर जाकर अपना मत देता है और नीचे आता है। यहां वह टेलीफोन भी है जिससे विजेताओं को फोन कर बताया जाता है कि वो नोबेल के लिए चयनित किए जा चुके हैं।

### क्या है यह अभियान

1. **ICAN** एक गैर लाभकारी संगठन की तरह काम करता है। इसमें दुनिया के कई छोटे समूह भी काम करते हैं।

**भारत में इन दो व्यक्तियों को मिल चुका है शांति पुरस्कार**

1. मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था।
2. 1928 में वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों की खूब मदद की।
3. गरीब और बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई और कुछ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों और दीन-दुखियों के लिए निर्मल हृदय नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी।
4. कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ था। सत्यार्थी भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बाचाओं आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद विश्व भर के 144 देशों के 83 हजार से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया।
5. कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के लिए किए गए बेहतर कार्यों को देखते हुए 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2. 10 साल पहले यह संस्था अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और 101 देशों में इसके 468 पार्टनर ग्रुप हैं।
3. दुनियाभर में लैंडमाइन के इस्तेमाल को रोकने के लिए जारी प्रयासों से प्रेरित होकर इस संगठन की नींव पड़ी।
4. **ICAN** के समर्थकों में दलाई लामा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटु, यूएन के पूर्व महासचिव बान की-मून समेत कई जानीमानी हस्तियां, अभिनेता शामिल हैं।
5. **ICAN** दुनियाभर की सरकारों को परमाणु हथियारों से पैदा हुए खतरे को लेकर आगाह कर रहा है। साथ ही इस अभियान के तहत सभी परमाणु संपन्न देशों से मिलकर परमाणु हथियारों को नष्ट करने की अपील की जा रही है।
6. इस कैंपेन का असर यह हुआ कि इसी साल जुलाई में परमाणु हथियारों पर रोक के लिए दुनियाभर के 122 देश यूएन संधि के समर्थन में आगे आए। हालांकि परमाणु संपन्न देशों ने अपने-अपने तर्क रखते हुए इसका विरोध किया।
7. यूएन संधि के तहत परमाणु हथियारों के विकास, टेस्टिंग, उत्पादन, निर्माण, भंडारण आदि पर रोक लगाने की बात कही गई है।
8. **ICAN** को नोबेल पुरस्कार उसके इसी प्रयास के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। इस कैंपेन की बदौलत ही दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की दिशा में धीमी गति से ही सही पर गंभीर प्रयास शुरू हुए हैं।
9. ICAN को नोबेल देने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों एवं परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वह किसी भी खतरे की स्थिति में उत्तर कोरिया को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ऐसे में इस कैंपेन का महत्व काफी बढ़ जाता है।
10. इस ग्रुप को पुरस्कार के तौर पर 1.1 मिलियन डॉलर की रशि मिलेगी। **ICAN** की कार्यकारी निदेशक बिट्रिस फिन ने कहा है कि परमाणु हथियारों से दुनिया के खत्म होने का खतरा है। जब तक ये हथियार रहेंगे, खतरा बरकरार रहेगा।
11. एक आंकड़े के मुताबिक रूस के पास 7000, अमेरिका के पास 6800, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 260, यूके के पास 215, पाकिस्तान के पास 130, भारत के पास 120, इमाइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं।

### अमेरिकी अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार

अमेरिका के दिग्गज अर्थशास्त्री रिचर्ड एच थेलर को इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने 9 अक्टूबर को अमेरिकन अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को नोबेल पुरस्कार का सम्मान दिए जाने की घोषणा की। अकेडमी ने कहा कि थेलर ने इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बीच एक पुल बनाया है। अवार्ड के रूप में उन्हें 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिया जाएगा। इस साल के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की दौड़ में भारत की ओर से रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल थे। 12 सितंबर, 1945 को जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री थेलर शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और अर्थशास्त्र में कई किताबें भी लिख चुके हैं।



### इस वर्ष नोबेल पुरस्कार

1. अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों जैफ्री सी हाल, माइकल रोसबाश तथा माइकल डब्ल्यू यंग को मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी विषय पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है।
2. फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी तरंगों की खोज के लिए रेनर बीस और बैरी बारिश को नोबेल का सम्मान मिला।
3. केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के हाई रेज्योलूशन संरचना निर्धारण के लिए क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार जैक्स ड्यूबोचेट, जोआचिम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन को दिया गया।
4. साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नॉवेलिस्ट काजुओ इशिगुरो को नोबेल पुरस्कार मिला।
5. आईसीएन को शांति का नोबेल पुरस्कार दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद भयावह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उसके प्रयासों की वजह से दिया गया है।

### इंडियाज मिलियन डेथ स्टडी

भारत में 2005 से 5 वर्ष से कम आयु के 10 लाख बच्चों को निमोनिया, डायरिया, नवजात शिशु संक्रमण, जन्म के समय दम घुटने/अभिधात, खसरे और टिटनेस से होने वाली मृत्यु से बचाया है। लैनसेट पत्रिका के ताजा अंक में प्रकाशित अध्ययन 'इंडियाज मिलियन डेथ स्टडी' ऐसा पहला अध्ययन है जिसको प्रत्यक्ष रूप से भारत में बच्चों की कारण विशेष मृत्यु में हुए बदलावों का अध्ययन किया गया है। इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लागू किया गया है और इसमें 2000-15 के बीच के अक्समात चुने गए घरों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय रूप में बच्चों की कारण विशेष मृत्यु का अध्ययन किया गया है।

**क्या है**

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रथमिकता के रूप में तय स्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव मृत्यु में गिरावट में दिखा। निमोनिया और डायरिया से होने वाली मृत्यु में 60 प्रतिशत से अधिक (कारगर इलाज के कारण) की गिरावट आई। जन्म संबंधी स्वासं कठिनाई और प्रसव के दौरान अभिधात से होने वाली मृत्यु में **66 प्रतिशत** (अधिकतर जन्म अस्पतालों में होने के कारण) की कमी आई।
2. खसरे और टिटनेस से होने वाली मृत्यु में **90 प्रतिशत** (अधिकतर विशेष टीकाकरण अभियान के कारण) की कमी आई। अध्ययन में कहा गया है नवजात शिशु कि मृत्यु दर (1000 प्रति जन्म) में 2000 के 45 शिशुओं से 2015 में 27 हो गई (3.3 प्रतिशत वार्षिक गिरावट) और 1-59 महीने के बच्चों की मृत्यु दर 2000 के 45.2 से गिरकर 2015 में 19.6 रह गई(5.4 प्रतिशत वार्षिक गिरावट)।
3. 1-59 महीने के बच्चों के बीच निमोनिया से होने वाली मृत्यु में **63 प्रतिशत** की कमी आई। डायरिया से होने वाली मृत्यु में 66 प्रतिशत तथा खसरे से होने वाली मृत्यु में 90 प्रतिशत से अधिक कमी आई।
4. यह गिरावट लड़कियों में रही। लड़कियों में गिरावट संकेत देता है कि भारत में लड़के और लड़कियां समान संख्या में मर रही हैं। यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी सुधारी स्थिति है।
5. 1-59 माह के बच्चों में नियमोनिया तथा डायरिया से होने वाली मृत्यु में 2010 व 2015 के बीच महत्वपूर्ण कमी आई। यह कमी राष्ट्रीय वार्षिक गिरावट को 8-10 प्रतिशत के औसत से रही। गिरावट विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब राज्यों में दिखी।
6. मिलियन डेथ स्टडी में प्रत्यक्ष रूप से **1.3 मिलियन (13 लाख)** घरों में मृत्यु के कारणों की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग की गई। 2001 से 900 कर्मियों द्वारा सभी घरों में रह रहे लगभग 1 लाख लोगों के साक्षात्कार लिए गए जिनके बच्चों की मृत्यु हुई थी (लगभग 53,000 मृत्यु जीवन के पहले महीने में हुई तथा 1-59 महीनों में 42,000

मृत्यु)। मृत्यु की मॉनिटरिंग में स्थानीय भाषा में आधे पन्ने में बीमारी के लक्षण और उपचार की जानकारी के साथ साधारण दो पन्नों का एक फार्म तैयार किया गया।

## स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वच्छता पखवाड़े के दौरान बेहतरीन योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अंतरमंत्रालय प्रदर्शन में इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2017 से 15 फरवरी, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया था। स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर, 2017 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

### क्या है

- स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान मंत्रालय के कार्यालयों, केंद्र सरकार के अस्पतालों, 36 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के जनस्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां चलाई गई।
- इसके अतिरिक्त जनजागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वयंसेवी संगठनों, विद्यार्थियों और समुदाय के लोगों की भागीदारी प्रशंसनीय रही। स्वच्छता आंदोलन के लिए इन गतिविधियों का योगदान उल्लेखनीय रहा।
- स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी.नड्डा ने 15 फरवरी, 2017 को मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विशेष स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया।
- मंत्री महोदय ने मंत्रालय के स्टाफ के साथ निर्माण भवन के गलियारों की सफाई गतिविधियों में हिस्सा लिया और मंत्रालय के विभिन्न कमरों और क्षेत्रों में स्वच्छता का जायजा लिया। मंत्रालय की विभिन्न विभागों की गैर वांछित और पुरानी फाइलों का निपटान किया गया।
- मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल, 2016 में आरंभ किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता गतिविधियों की पूर्व कार्ययोजना के लिए मंत्रालय ने पहले ही एक वार्षिक कलेंडर जारी किया।
- मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता समीक्षा के तहत ऑन लाइन निगरानी प्रणाली के तहत योजना चित्र, वीडियो अपलोड किए गए जिसमें स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी मुहैया कराई गई, इसे शेयर भी किया गया।

## कछुआ शरणस्थली स्थापित की जाएगी

गंगा नदी में समृद्ध जलीय जैव विविधता पर मानवजनित दबाव से रक्षा के लिए नमामि गगे कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद में कछुआ शरणस्थली विकसित करने और संगम पर नदी जैवविविधता पार्क विकसित करने को मंजूरी दी गई है। 1.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना में गंगा-यमुना और सरस्वती के संगम पर नदी जैव विविधता पार्क विकसित किया जाएगा और कछुआ पालन केंद्र (त्रिवेणी पुष्प पर स्थायी नर्सरी तथा अस्थायी वार्षिक पालन) स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता लाने की भी स्वीकृति दी गई है।

### क्या है

- यह परियोजना एक आवश्यक मंच प्रदान करेगी ताकि आगंतुक अपनी पारिस्थितिकीय प्रणाली, अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जान सकें और पर्यावरण के साथ सह-अस्तित्व की जटिलता को समझ सकें। इस परियोजना से लोग महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। परियोजना में गंगा नदी के बारे में ज्ञान में आ रही कमी को रोकने के कार्य को उत्साह से किया जाएगा। यह परियोजना 100 प्रतिशत केंद्र पोषित परियोजना है।

2. गंगा नदी में घड़ियाल, डॉलफिन तथा कछुए सहित 2000 जलीय प्रजातियां हैं जो देश की आबादी की 40 प्रतिशत की जीवन रेखा की समृद्ध जैव विविधता को दिखाती हैं।
3. इलाहाबाद में गंगा और यमुना में विलुप्त हो रही कछुओं की प्रजातियां (बतागुर कछुगा, बतागुर धोनगोका, निल्सोनिया गैरेटिका, चित्रा इडिका, हरदेला टूरजी आदि) हैं।
4. गंगा और यमुना में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति - गांगेर डॉलफिन, घड़ियाल हैं तथा असंख्य प्रवासी और आवासीय पक्षियों ने भी बसेरा बना रखा है।

## भारतीय मिला को एसओएआर अवार्ड

अमेरिका में भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक को सिर और गर्दन के कैंसर पर अनुसंधान के लिए 81 लाख डॉलर (52.74 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया गया है। अनुसंधान से रोगियों के जीवित बचने की दर में सुधार किया जा सकेगा। निशा डिसिल्वा को सिर और गर्दन के कैंसर को फैलने से रोकने और इसकी पुनरावृत्ति पर लगाम लगाने वाली आण्विक विधियों पर जारी उनके अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित 'स्स्टेनिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रिसर्च' (एसओएआर) अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिसिल्वा को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल एंड क्रेनियोफेशियल रिसर्च (एनआईडीसीआर) से अनुदान राशि आठ साल में वितरित की जाएगी। वह अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में चिकित्सकीय वैज्ञानिक हैं।

### क्या है

1. उनका लक्ष्य कैंसर रोगियों के बचने की दर में सुधार करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की डीन लौरी मैक्काउली ने कहा कि प्रतिष्ठित एसओएआर अनुदान यह बताता है कि डॉ. डिसिल्वा के अनुसंधान रिकॉर्ड और आगे बढ़ने की उनकी क्षमता को किस तरह देखा जा रहा है।
2. डिसिल्वा ने कहा कि सिर और गर्दन का कैंसर विश्व में छठा सर्वाधिक होने वाला कैंसर है।
3. इसके हर साल लगभग छह लाख नए मामले आते हैं। उन्होंने कहा कि रोग निदान के पांच साल के भीतर लगभग आधे रोगियों की मौत हो जाती है।

## और अमीर हुए भारत के रईस

दसवें साल लगातार रिलायंस इंस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी फोर्ब्स की लिस्ट में अमीरों की सूची में बरकरार हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फोर्ब्स के ग्लोबल गेम चेंजर की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। उनकी संपत्ति करीब 38 बिलियन डॉलर (करीब 2.5 लाख करोड़) आंकी गई है। दूसरे नंबर पर 19 बिलियन की संपत्ति के साथ विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं और तीसरे स्थान पर हिंदुजा ब्रदर्स हैं। अजीम प्रेमजी ने पिछले साल से दो कदम आगे की ओर बढ़ाया है जबकि सन फार्मा के दिलीप शांघवी पीछे खिसक गए हैं। पिछले साल दूसरे स्थान पर रहे सांघवी इस साल 12.1 बिलियन की संपत्ति के साथ 9वें पायदान पर हैं।

### फोर्ब्स की सूची के अनुसार टॉप टेन अमीर भारतीय-

1. मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज) संपत्ति- 38 बिलियन डॉलर
2. अजीम प्रेमजी (विप्रो) संपत्ति- 19 बिलियन डॉलर
3. हिंदुजा ब्रदर्स (अशोक लेलैंड) संपत्ति- 18.4 बिलियन डॉलर
4. लक्ष्मी मित्तल (आर्सेलर मित्तल) संपत्ति- 16.5 बिलियन डॉलर
5. पल्लोनजी मिस्त्री (शपूर्जी पल्लोनजी ग्रुप) संपत्ति- 16 बिलियन डॉलर
6. गोदरेज फैमिली (गोदरेज ग्रुप) संपत्ति- 14.4 बिलियन डॉलर
7. शिव नादर (एचसीएल टेक्नॉलजीज) संपत्ति- 13.6 बिलियन डॉलर
8. कुमार बिड़ला (आदित्य बिड़ला ग्रुप) संपत्ति- 12.6 बिलियन डॉलर
9. दिलीप शांघवी (सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज) संपत्ति- 12.1 बिलियन डॉलर

10. गौतम अडाणी (अडाणी पोर्ट एंड सेज) संपत्ति- 11 बिलियन डॉलर

### अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल शीर्ष पर

बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में 7 महिलाओं का नाम है। इस सूची में भारत की पहली अमीर महिला के रूप में सावित्री जिंदल एंड फैमिली 7.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 16वें स्थान पर हैं। अमीर भारतीय की सूची में लगातार दसवें साल मुकेश अंबानी 38 अरब डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। 'इंडिया रिच लिस्ट 2017' में सावित्री जिंदल के बाद गुप्ता परिवार 3.45 अरब डॉलर के साथ 40 वें स्थान पर हैं। जून 2017 में देश बंधु गुप्ता के निधन के बाद उनके द्वारा स्थापित फार्मा प्रमुख ल्यूपिन में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी से गुप्ता परिवार का भाग्य चमका है। उनकी पत्नी मंजु देश बंधु गुप्ता फिलहाल ल्यूपिन के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

**क्या है**

- प्रतिष्ठित अमीरों की सूची में विनोद और अनिल राय गुप्ता एंड फैमिली भी 3.11 अरब डालर की संपत्ति के साथ 48 वें स्थान पर हैं। इसके बाद जैन परिवार 3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 51 वें स्थान पर है। फोर्ब्स के अनुसार, जैन परिवार मीडिया हाउस बेनेट एंड कोलमैन को नियंत्रित करता है, जो कि इंदु जैन के पुत्र समीर और विनीत भाइयों द्वारा चलाए जाते हैं।
- अमलगैमेशन परिवार को 2.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 63 वें स्थान पर रखा गया। यह समूह ट्रैक्टर निर्माता टीएफई और डीजल इंजन कंपनी सिम्पसन एंड कंपनी के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय एस अनंतरामकृष्णन ने की थी।
- समूह के प्रमुख एस अनंतरामकृष्णन के बेटे ए.कृष्णमूर्ति हैं। सबसे धनी भारतीयों महिलाओं की सूची में लीना तेवारी को 2.19 अरब डॉलर के साथ 71 वें स्थान पर रखा गया है।
- तिवारी यूएसवी इंडिया की मालकिन हैं, जो उनके दिवंगत पिता विठ्ठल गांधी ने 1961 में रेवलॉन के साथ स्थापित की थी। मजूमदार-शॉ, 2.16 अरब डॉलर के साथ, 72 वां स्थान पर हैं। वे भारत की सबसे अमीर आत्मउद्यमी महिला हैं जिन्होंने 1978 में बायोफर्म फर्म बायोकॉन की स्थापना की। फोर्ब्स के अनुसार, बायोकॉन कंपनी मलेशिया के जोहर में एशिया का सबसे बड़ा इंसुलिन निर्माता है।

### Hang till Death को बदलने की मांग पर नोटिस

मृत्युदंड के लिए दिए जाने वाले फांसी की सजा से कम कष्टकर दूसरा तरीका अपनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके लिए वकील रिषी मल्होत्रा ने याचिका दाखिल की है। मल्होत्रा ने याचिका में मृत्युदंड के लिए फांसी को क्रूर तरीका बताया है और इसकी जगह किसी दूसरे विकल्प को अपनाने की मांग की है।

**क्या है**

- याचिका में यह भी कहा गया है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक्ट में मृत्युदंड में दो विकल्प होते हैं। फांसी या गोली मारना, जबकि आइपीसी और सीआरपीसी में सिर्फ फांसी का प्रावधान है।
- वहां जजों को विवेकाधिकार है, जबकि यहां नहीं है। अलग-अलग कानूनों में अलग अलग व्यवस्था भेदभाव और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मल्होत्रा का कहना है कि मृत्युदंड देने का फांसी का तरीका खत्म करके कोई और तरीका अपनाया जाए।
- मल्होत्रा ने मरने तक फांसी पर लटकाए रखने का प्रावधान करने वाली सीआरपीसी की धारा 354(5) को रद करने की मांग करते हुए कहा है कि ये मौत देने का सबसे क्रूर और अमानवीय तरीका है। उनका कहना है कि अमेरिका के 35 राज्यों में मृत्युदंड में फांसी खत्म कर उसकी जगह गोली मारने या इलेक्ट्रिक चेयर के तरीके को अपनाया गया है।

4. फांसी देने के लिए अपनाये जाने वाले तरीके और सजा भुगतने जा रहे दोषी की मनोदशा की चर्चा करते हुए मल्होत्रा कहते हैं कि दोषी को फांसी के लिए डायस तक ले जाते हैं। उसके मुंह को काले कपड़े से ढंका जाता है। फांसी देने से पहले फंदा जांचा जाता है, ड्राप जांचा जाता है यानि दोषी के बजन के बराबर का ड्राप डाल कर देखा जाता है। फांसी के बाद शरीर को आधे घटे लटका कर रखा जाता है। यह प्रक्रिया काफी क्रूर है।

## इस राज्य में नवजात मृत्यु दर सबसे ज्यादा

यूपी के गोरखपुर, बरेली, झारखण्ड के जमशेदपुर और राजस्थान में जुलाई से अगस्त के महीने में नवजातों की मौत ने कितनी मांओं की गोद सूनी कर दी थी, अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सर्वे में सामने आया है कि उत्तराखण्ड में नवजातों का मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 9 राज्यों में हुए सर्वे के मुताबिक देवभूमि में नवजातों के दम तोड़ने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है।

### क्या है

1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसआरएस ये सर्वे कराता है और इस सर्वे में पाया गया है कि उत्तराखण्ड में अगर साल भर में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 38 की मौत हो जाती है।
2. इस मामले में ये राज्य 4 प्लाइंट आगे निकल गया है, जबकि बाकी कई राज्य जैसे असम, यूपी और मध्यप्रदेश में इस संख्या में कमी आई है।
3. बिहार, असम, यूपी, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान इन राज्यों में ये सर्वे हुआ है। सभी राज्यों के आंकड़ों को एक साथ देखने के बाद यही खुलासा हुआ है कि उत्तराखण्ड में सबसे ज्यादा नवजातों की मौत हो रही है। वहाँ, मध्यप्रदेश, यूपी और असम में काफी सुधार देखने को मिला है।
4. एमपी में 50 से आंकड़ा 47 हो गया, यूपी में 46 से 43 और असम में 47 से 44 ओडिशा में 46 से 44 और असम में भी बहुत नीचे गिर गया है।
5. आईएमआर का आरोप है कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में काफी लापरवाही के मामले सामने आते हैं। हरिद्वार और उत्तराखण्ड के बाकी छोटे जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास में काम नहीं हो रहा है।

## प्रादेशिक सेना का 68वां स्थापना दिवस

प्रादेशिक सेना (टीए) ने 9 अक्टूबर को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। टीए की परम्परा के अनुसार, एडीजी टीए मेजर जनरल डी.ए. चतुर्वेदी ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के प्रति सम्मान व्यक्त किया। स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में कई समारोहों का आयोजन किया गया। दिल्ली में टीए ने 02 अक्टूबर, 2017 को नागरिक सेना की सच्ची भावना के अनुरूप अर्द्ध मैराथन का आयोजन किया तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया। इस समारोह में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एवं 21 किलोमीटर की स्पर्धाएं शामिल थीं तथा इसे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल एके. भट्ट एवं लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) कपिल देव द्वारा दिल्ली कैंट के आर्मी परेड ग्राउंड में झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्पर्धा में रक्षा से जुड़े 3000 जवानों तथा उनके परिवार जनों ने विभिन्न वर्गों में भाग लिया। टीए के सिमफोनी बैंड ने 08 अक्टूबर, 2017 को इंडिया गेट पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसने भारी संख्या में लोगों को आकर्षित किया, जो बैंड के शानदार संगीत से सम्मोहित हो गये और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। टीए कार्यकर्ताओं की नागरिक सेना है, जिसमें देश की रक्षा के प्रति योगदान देने का जज्बा है। प्रादेशिक सेना देश के युवाओं को उनके अतिरिक्त समय में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय आपातकालों और आंतरिक अराजकता की स्थिति में देश की सेवा करने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है।

### क्या है

1. प्रादेशिक सेना निकोबार में एक पैदल सेना बटालियन (टीए) तथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित क्षेत्र में एक पारिस्थितिकीय कार्यबल बटालियन के निर्माण के द्वारा अपनी उपस्थिति को विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।

2. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए एक अंगभूत पारिस्थितिकीय कार्यबल की स्थापना का मामला भी मंजूरी के अंतिम चरण में है। इस प्रकार की नई स्थापना और विशेष रूप से नमामि गंगा मिशन के लिए इकाई की स्थापना प्रादेशिक सेना को राष्ट्रीय ध्येय की दिशा में व्यापक रूप से योगदान देने में समर्थ बनाएगा।
3. निकट भविष्य में प्रादेशिक सेना की अनूठी ताकत आपदा प्रबंधन के दौरान राष्ट्रीय प्रयासों की स्थापना के लिए एक आदर्श मंच साबित हो सकती है।
4. प्रादेशिक सेना ने 1962, 1965 एवं 1971 की पिछली लड़ाइयों के दौरान कई गौरवशाली कार्यों को अंजाम दिया तथा सराहनाएं बटोरीं। इसने ऑपरेशन पवन, विजय एवं पराक्रम में अपनी हिम्मत एवं साहस का परिचय दिया।
5. विभिन्न ऑपरेशनों में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए टीए के जवानों को अनगिनत पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर 164 पैदल सेना बटालियन (टीए) (एच एवं एच) नागा के मेजर डेविड मेनलन को कीर्ति चक्र (मरणोपरांत) तथा टीए की तीन इकाइयों को प्रदान किये गये आर्मी कमांडर के यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रादेशिक सेना की बहादुरी तथा निरंतर भावना के परिचायक हैं।
6. 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रादेशिक सेना अधिनियम को संविधान सभा द्वारा 18 अगस्त, 1948 को कानून का रूप दिया गया, जिसका परिणाम वर्तमान प्रादेशिक सेना के गठन के रूप में सामने आया।
7. प्रादेशिक सेना की विभागीय इकाइयों ने रेल संचार, तेल एवं प्राकृतिक गैस परिष्करण और आपूर्तियों के समर्थन में हमेशा कारगर भूमिका निभाई है।
8. पारिस्थितिकीय कार्यबल अपने निर्धारित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर पर्यावरण चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते रहे हैं और सराहनीय परिणाम अर्जित किये हैं।
9. पारिस्थितिकीय बल ने उत्तराखण्ड के मलारी क्षेत्र के सीमावर्ती गांव के लोगों की सहायता के लिए अखरोट एवं चिलगोजा के पौधा रोपण की अनूठी पहल की है, जिससे कि उन्हें उनके जीवन यापन में सहायता की जा सके तथा आर्थिक प्रवास से रोका जा सके।

### मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2017

भारतीय मूल की मधु वल्ली ने मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2017 का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय हिप-हॉप कलाकार वर्जीनिया की जार्ज मैसन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रही हैं। न्यूजर्सी में हुई इस सौंदर्य प्रतियोगिता में फ्रांस की स्टेफनी मैडवने दूसरे नंबर पर रहीं।

#### क्या है

1. प्रतियोगिता में 18 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया, जिसमें गुयाना की संगीता बहादुर तीसरे नंबर पर रहीं।
2. खिताब जीतने के बाद मधु ने कहा, मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच सेतु बनना चाहती हूं। उन्होंने कहा, मैं अपने दोनों देशों (भारत और अमेरिका से) से प्यार करती हूं और मैं हमेशा दोनों का नेतृत्व करने का तरीका खोजना चाहती थी।
3. उनकी एक एल्बम एक दिन पहले ही जारी हुई थी। उन्होंने कहा कि वह एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनना चाहती हैं।

### FTII के नए अध्यक्ष

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह गजेंद्र चौहान का स्थान लेंगे। उनकी इस नियुक्ति पर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने कहा, 'वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं। अनुपम अच्छे शिक्षक साबित होंगे।'

#### क्या है

1. गजेंद्र चौहान का कार्यकाल मार्च में पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए किसी तरह का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ था।
2. गजेंद्र चौहान को जब इस संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया था तो वहां कई वर्षों से काबिज छात्रों ने अभिनय जगत में उनकी काबिलियत पर सवाल उठाते हुए भारी विरोध किया था।

### **वरिष्ठ वकील का दर्जा के लिए सुप्रीम कोर्ट का मानक**

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के लिए स्वयं और देश के 24 हाईकोर्ट के लिए मानक तय कर दिये हैं। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए 11 दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब वरिष्ठता के दर्जे पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एक स्थाई समिति होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेंगे। वरिष्ठता का दर्जा देने से पहले वकील की काबिलियत, अनुभव, व्यक्तित्व और अनुकूलता के आधार पर अंक दिये जाएंगे। इतना ही नहीं वरिष्ठता के प्रस्ताव को वेबसाइट पर डालकर सुझाव भी मंगाए जाएंगे। तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले ये दिशानिर्देश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह की याचिका का निपटारा करते हुए दिये। जयसिंह ने वरिष्ठता का दर्जा देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाये थे और पारदर्शी तंत्र बनाने की मांग की थी। कुछ और याचिकाएं भी थीं जिनमें ऐसी मांग की गई थी।

#### **क्या है**

1. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वरिष्ठता का दर्जा देने के लिए कमेटी फार डिजिनेशन आफ सीनियर्स विचार करेगी।
2. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश और अटार्नी जनरल होंगे। ये चार सदस्य बार एसोसिएशन से एक सदस्य को नामित करेंगे। कुल पांच सदस्यों की कमेटी होगी।
3. हाईकोर्ट के मामले में कमेटी की अध्यक्षता संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसके अलावा दो वरिष्ठ न्यायाधीश और एडवोकेट जनरल होंगे। ये चारों सदस्य मिल कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक सदस्य को नामित करेंगे। इस कमेटी को मदद करने के लिए एक सचिवालय होगा।
4. स्थाई समिति वकील के ब्योरे के आधार पर वकील का साक्षात्कार लेगी और अंकों के आधार पर आकलन करेगी। स्थाई समिति सारे आकलन के बाद लिस्ट तैयार करके फुल कोर्ट की मंजूरी के लिए भेजेगी।
5. फुल कोर्ट इस पर सीक्रेट बैलेट या बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी। फुल कोर्ट से जिन नामों को मंजूरी नहीं मिल पाएंगी उन्हें दो वर्ष बाद दोबारा से आवेदन करने का हक होगा। इतना ही नहीं कदाचार के मामलों में फुल कोर्ट वरिष्ठता के दर्जे की पुर्ण समीक्षा कर सकता है और उसे वापस भी ले सकता है।

### **एशिया कप में भारत की दूसरी जीत**

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 13 अक्टूबर को हीरो एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट के दूसरे मैच में बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में विजयी अभियान जारी रखा। मौलाना भशानी नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने मेजबान टीम बांग्लादेश को 7-0 से हराया। भारत ने शुरुआत से ही इस मैच पर अपना दबदबा बनाया हुआ था। गुरजंत सिंह ने सातवें मिनट में फील्ड गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद, 11वें मिनट में एस.वी. सुनील के पास को आकाशदीप ने बांग्लादेश के पाले में सफल रूप से पहुंचाया और भारत को 2-0 से आगे कर दिया। ललित उपाध्याय ने दो मिनट बाद ही 13वें मिनट में भारत के लिए तीसरा गोल किया। दूसरे क्वार्टर में 20वें मिनट में गुरजंत की मदद से अमित रोहिदास ने भारत के लिए चौथा गोल किया।

### **'नेक्स्ट जेनरेशन लीडर्स' लिस्ट में एकमात्र भारतीय**

कारगील युद्ध में शहीद हुए सेना के अधिकारी की बेटी गुरमेहर कौर को टाइम्स मैगजीन ने नेक्स्ट जेनरेशन लीडर्स लिस्ट-2017 में जगह दी है। गुरमेहर को भविष्य की नेत्री माना गया है। गुरमेहर इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के

रामजस कॉलेज में छात्रों के साथ हुए मार-पीट को लेकर हुए विरोध के दौरान चर्चा में आई थीं। गुरमेहर को इसके अलावा बोलेन की आजादी का योद्धा घोषित किया है। इसमें सबसे रोचक बात ये है कि वो इस लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं।

**क्या है**

1. मैगजीन के 12 अक्टूबर को जारी हुए अंक में 10 पुरुषों और 10 महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें उन लोगों को जगह दी गई है जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिससे दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिला हो। गुरमेहर को लिस्ट में दूसरे पायदान पर रखा गया है।
2. मैगजीन में छपे गुरमेहर के बयान के मुताबिक उनका कहना है, 'मुझे क्यों चुप रहना चाहिए? न ही मुझे इसकी कोई जरूरत थी, मुझे धक्का दे कर यहां तक लाया गया था। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जो कह रही हूं वो लोग सुनते हैं और अगर मेरे पास कहने को कुछ बेहतर है तो वो बात मुझे क्यों नहीं कहनी चाहिए।
3. गैरतत्व है कि गुरमेहर इसी साल फरवरी में उस वक्त चर्चा में आई थीं जब उन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध दर्ज किया था।

### अब सीबीएसई स्कूलों की भी होगी रैकिंग

उच्च शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर सीबीएसई स्कूलों की भी अब रैकिंग होगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दोनों ही विद्यालय संगठनों से इसके लिए एक गाइड लाइन तैयार करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने की तैयारी की जाए। देश भर में मौजूदा समय में 1128 केंद्रीय विद्यालय और 589 नवोदय विद्यालय हैं।

**क्या है**

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस पहल को स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्कूलों में बीच इस प्रतिस्पर्धा के शुरू होने इसके पठन-पाठन में सुधार होगा। साथ ही ऐसे विद्यालयों को भी चिन्हित करने में मदद मिलेगी, जो अपनी किसी न किसी कमज़ोरी के चलते पिछड़ रहे हैं।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच कराई गई ऐसी ही प्रतिस्पर्धा से इनमें सुधार सामने आने के बाद यह पहल शुरू की गई है। मौजूदा समय में देश भर में सीबीएसई से संबद्ध 17 हजार से ज्यादा स्कूल हैं।
3. इन आधारों पर होगी रैकिंगमंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो स्कूलों की रैकिंग तय करने का जो आधार होगा, उनमें विद्यालय का इफ्रास्ट्रक्चर, खेलकूद की सुविधाएं, छात्रों के क्लास रूम, पुस्तकालय आदि शामिल हैं।
4. इसके अलावा एक शिक्षक पर छात्रों की औसत संख्या, शिक्षकों की योग्यता, पास आऊट होने वाले छात्रों का प्रतिशत, प्रोफेशनल कोर्सों के लिए छात्रों के चयन का प्रतिशत और फीस जैसी जानकारियां शामिल होंगी।